

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1114
रविवार, 20 सितंबर, 2020/29 भाद्रपद, 1942 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

भारत में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र पर कोविड-19 का प्रभाव

1114. श्री सुजीत कुमार:

डा. सस्मित पात्रा:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारत में पर्यटन क्षेत्र पर विशेषकर राजस्व, पर्यटकों की संख्या, पर्यटन कम्पनियों के बंद होने और आतिथ्य क्षेत्र के संबंध में कोविड-19 के प्रभावों का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र के साथ-साथ इससे जुड़े आतिथ्य क्षेत्र को कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से उबारने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): पर्यटन क्षेत्र पर राजस्व, पर्यटक आगमन, पर्यटक कंपनियों तथा आतिथ्य क्षेत्र के बंद होने के प्रभाव के संबंध में आकलन के लिए कोई औपचारिक अध्ययन शुरू नहीं किया गया है । तथापि उद्योग जगत के हितधारकों के साथ विचार-विमर्श तथा विचार-मंथन सत्र के अनेक दौर आयोजित किए जाने के बाद राजस्व, विदेशी मुद्रा तथा नौकरियों के व्यापक रूप से नुकसान का संकेत मिलता है । इस क्षेत्र के अत्यधिक असंगठित स्वरूप के मद्देनजर आंकड़ों के रूप में प्रभाव का आकलन समुचित समय पर ही किया जा सकेगा ।

(ख): भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों और मंत्रालयों द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज अनुबंध । में दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त पर्यटन क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए उठाए गए अन्य कदम अनुबंध II में दिए गए हैं ।

भारत में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र पर कोविड-19 का प्रभाव के संबंध में दिनांक 20.09.2020 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1114 के भाग (ख) के उत्तर में विवरण

भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों तथा मंत्रालयों द्वारा घोषित पैकेज निम्नानुसार हैं :

- आरबीआई ने आवधिक ऋणों पर स्थगन 31 अगस्त 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है ।
- सरकार ने इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है जिसके तहत एमएसएमई के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का कॉलेटरल फ्री ऑटोमेटिक ऋण उपलब्ध कराया गया है । इस ऋण की अवधि 4 वर्ष होगी तथा 12 माह की स्थगन अवधि होगी।
- सरकार ने उन संगठनों के लिए तीन महीने के लिए भविष्यनिधि योगदान में छूट दी है जिनके पास 100 से कम कामगार हैं तथा उनमें से 90% कर्मचारियों के वेतन 15000 रुपए से कम है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत नियोजक तथा कर्मचारी दोनों के पीएफ अंशदान को मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है । यह उन सभी संस्थानों के लिए अगले 3 माह अर्थात सितंबर 2020 तक है जो ई पी एफ ओ द्वारा कवर होते हैं।
- अक्टूबर 2020 तक टीसीएस का स्थगन ।
- 5 करोड़ रु. तक की कंपनियों के लिए किसी दंडात्मक ब्याज के बिना 3 माह तक रिटर्न फाइल करना स्थगित किया गया और शेष के लिए 9% के दंडात्मक ब्याज का प्रावधान किया गया है ।
- केंद्र सरकार ने व्यवसाय की निरंतरता और उत्थान सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट के मद्देनजर आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम तथा जी एस टी अधिनियम के अंतर्गत अलग-अलग अवधि के लिए विभिन्न विनियामक अपेक्षाओं से छूट भी दी है ।

भारत में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र पर कोविड-19 का प्रभाव के संबंध में दिनांक 20.09.2020 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1114 के भाग (ख) के उत्तर में विवरण

पर्यटन क्षेत्र में कोविड-19 के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- i. कोविड-19 सुरक्षा तथा स्वच्छता के संबंध में जागरूकता पैदा करने प्रशिक्षण और दिशा निर्देशों के अनुपालन के आकलन के लिए विस्तृत प्रचालन संबंधी दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं । इस कार्यक्रम का लक्ष्य आतिथ्य उद्योग विशेष रूप से छोटी तथा मझौली इकाइयों को बहाल होने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में सहायता देने के लिए क्षमता निर्माण करना है ।
- ii. सभी अवर्गीकृत आवास इकाइयों के समन्वयन और उनका पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए देशभर में विभिन्न आवास इकाइयों की एक सुदृढ़ सूचना प्रणाली/व्यापक डाटाबेस तैयार किया गया है ।
- iii. होटलो, रेस्तरां, बेड एंड ब्रेकफास्ट/होम स्टे तथा पर्यटन सेवाप्रदाताओं के लिए प्रचालन संबंधी सिफारिशें तैयार की गई हैं और व्यवसाय की निर्बाध बहाली सुनिश्चित करने के लिए 8 जून, 2020 को जारी की गई है ।
- iv. ऐसे होटलों तथा अन्य आवास इकाइयों जिनका परियोजना अनुमोदन/पुनःअनुमोदन तथा वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने वाला है उनकी अनुमोदन अथवा प्रमाणन की वैधता अवधि को 30 सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है ।
- v. मंत्रालय ने क्यू सीआई के सहयोग से होटलों, रेस्तरां, बेड एंड ब्रेकफास्ट तथा अन्य इकाइयों के सुरक्षित प्रचालन के लिए कोविड-19 तथा उसके पश्चात की स्थिति में जारी दिशा निर्देशों/ एसओपी के कारगर कार्यान्वयन के लिए साथी (सिस्टम फॉर एसेसमेंट, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री) नामक एक पहल की है ।
